ORIGINAL RESEARCH PAPER

Social Science

KEY WORDS: ग्रामीण विकास, स्मार्ट शहर, व्यवसाय

स्मार्ट और सतत ग्रामीण विकास

Avinash Tiwari Research Scholar, Department of Sociology, Shibli National PG College Azamgarh, India-276001.

Dr. Ziau Rahman Khan* Associate Professor, Department of Sociology, Shibli National PG College Azamgarh, India-276001. *Corresponding Author

ABSTRACT

भारत में, स्मार्ट शहरों के निर्माण के लिए हर जगह बहुत अधिक चर्चा और विचार-विमर्श हो रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट और टिकाऊ बनाने के लिए कम चर्चा होती है। ग्रामीण क्षेत्रों को स्मार्ट और टिकाऊ होना अत्यावश्यक है क्योंकि यहां भारत के बारे में संयुक्त रूप से कहा जाता है कि-"भारत गांवों में रहता है" और यदि किसान खुश हैं और केवल तभी शहरवासी खुश और समृद्ध होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में है, क्योंकि शहरी स्थान लगभग अपने संतृप्ति स्तर तक पहुँच चुके हैं। हमें स्मार्ट ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिरता को संरक्षित करने से शहरों और अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र पर लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा] और इससे स्मार्ट शहरों को भी क्षमता मिलेगी। केवल स्मार्ट शहर ही बनाएंगे जो विच्छेदन और संकट के सागर में अवसरों का एक द्वीप मात्र होगा जो टिकाऊ नहीं हो सकता।

परिचय

"भारत में 610 जिले हैं, (200 पिछड़े) 600,000 गाँव (125,000 पिछड़े)। भारत में लगभग 800 मिलियन लोग गांवों में रहते हैं और उनमें से कम से कम आधे लोग 35 साल से कम उम्र के हैं।"[1] सरकार ग्रामीण और आर्थिक रूप से गरीब क्षेत्रों के उत्थान की जिम्मेदारी ले रही है। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, पानी और स्वच्छता में सुधार के लिए बहुत सारे सार्वजनिक खर्च हो रहे हैं। हालांकि, ये प्रयास असमान और खंडित रूप से हो रहे हैं जिससे अधिकांश गांवों में बहुत सुधार नहीं हुआ है। स्मार्ट गांवों के डिजाइन और निर्माण की आवश्यकता है जो कल्याणकारी सेवाएं और रोजगार प्रदान करने में स्वतंत्र हों और दुनिया के बाकी हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़े हुए हों।

"एक स्मार्ट गांव निवासियों और व्यवसायों के लिए प्रभावी ढंग से वितरित दर्जनों सेवाओं का एक बंडल है। ये सेवाएं गाँव की जनसांख्यिकी और निवासियों के व्यवसाय के आधार पर विशिष्ट हो सकती हैं।"[2] ये सेवाएं जैसे कि बिजली, पानी, इमारतें, खुदरा, स्वास्थ्य देखभाल, आदि कई दशकों पहले बनाई गई थीं। नए डिजाइन, प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन मॉडल का उपयोग मौजूदा लोगों को अपग्रेड करने और निर्माण में किया जाना चाहिए। "इसके लिए मानकीकरण, आईटी और सेंसर नेटवर्क का उपयोग आवश्यक है। रणनीति और एकीकृत योजना की आवश्यकता है जो उपयुक्त शासन मॉडल का उपयोग करते हुए इन सभी लोगों (लगभग 70 प्रतिशत भारतीय आबादी गांवों में रहती है) के गतिविधियों का करे"[3]। इसलिए यह स्वाभाविक है कि इसमें समावेशी विकास के लिए, सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। केवल 'स्मार्ट सिटी' बनाने पर जोर देना न्यायपूर्ण नहीं हो सकता। हमें 'स्मार्ट गांवों' के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। गांवों की स्थिरता को बनाए रखना, शहरों को लंबे समय तक सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।

"हाल के दिनों में, फसल खराब होने के कारण किसानों की आत्महत्या के अधिक मामले सामने आए हैं। आजादी के 70 साल बाद भी, हमारे पास समर्थन और मार्गदर्शन प्रणाली का अभाव है, और न ही हमारे पास किसानों के लिए पेशेवर परामर्श है।"[4] उनमें से कई के पास आय का कोई माध्यमिक स्रोत नहीं है जो एक प्रमुख लक्ष्य हों चाहिए । कम पारिश्रमिक खेती (बड़ी भूमि जोत के मामले में) को छोड़कर गाँवों में नौकरी के अवसरों की कमी, गाँव के युवाओं को शहरों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर करती है। वहाँ, उनमें से कई जीवन के उचित गुणवत्ता का आनंद नहीं ले पाते हैं क्योंकि वे केवल निर्वाह नौकरियों को प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं। प्रवासन भी प्रत्यक्ष है क्योंकि वे बेहतर नौकरी की उम्मीद में शहरों में रहना जारी रखते हैं। लंबी अवधि के लिए गाँवों से पलायन होता है, गाँव की संस्कृति कमजोर पड़ने लगती है। जिससे शहरों में, अनियंत्रित प्रवासन, प्रदूषण, ट्रैफिक समस्या, अपराध और नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का बोझ बढ़ता है।

आजीविका की ओर

सर्वोच्च प्राथमिकता गांवों में युवाओं के लिए अवसरों का निर्माण होना चाहिए, जिससे शहरों में पलायन कम हो सके। खेती को एक पारिश्रमिक व्यवसाय बनाया जाना चाहिए, जिसमें मार्गदर्शन और छोटे किसानों को सलाह दी जाए कि वे किस प्रकार पारिश्रमिक कीमतों पर सर्वोत्तम उपज और मूल्य/बाजार प्राप्त कर सकते हैं। आय के द्वितीयक स्रोत को विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और नीम कीटनाशकों जैसी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचाया जाना चाहिए। प्रत्येक गांव में एक हेल्पडेस्क स्थापित किया जाय जो प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किसानों के प्रश्नों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए सबसे उपयोगी हो। इन सब के लिए उचित और योजनाबद्ध क्रियान्वयन का होना जरुरी है।

हमें एक इको-सिस्टम बनाना होगा जो युवाओं को उनके गांवों से काम करने के लिए प्रेरित करे । "BPO के द्वारा गावों में युवाओं को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। वहां के युवाओं को नया स्टार्टअप/ व्यवसाय आदि के लिए प्रेरित किया जा सकता है। कई नौकरियों में डिग्री के बजाय कंप्यूटर कौशल की आवश्यकता होती है। डाकघरों, ग्रामीण बैंकों और आईटी-सक्षम सेवाओं का डिजिटलीकरण उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया द्वारा समर्थित परियोजनाओं को गांवों तक पहुंचने के लिए एकीकृत एजेंसी के माध्यम से एकीकृत किया जाना चाहिए"[5]। उदाहरण के लिए, स्किल इंडिया युवाओं को राजमिस्त्री, यांत्रिकी, इलेक्ट्रीशियन और ड्राइवर के रूप में प्रशिक्षण के बाद अपने छोटे व्यवसाय शुरू करने या मरम्मत की दुकानें, पोल्ट्री और डेयरी फार्म, किराना स्टोर, टीहॉप्स,

ढाबा और जल्द ही चलाने के लिए सशक्त बना सकती है। भारत के शिल्प गाँवों में पनपते हैं, खासकर सहकारी उपक्रमों के रूप में। मिट्टी के बर्तनों, धातु शिल्प, बुनाई, आभूषण बनाने, लकड़ी के शिल्प, खोल शिल्प, बेंत शिल्प, कढ़ाई, हाथी दांत शिल्प, कांच शिल्प और कागज शिल्प आय के स्रोत हो सकते हैं। शहरों में गांवों की कला और शिल्प पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से बनाना असंभव है। निर्यात क्षमता का एक बड़ा सौदा यहां छिपा है। गावं के वरिष्ठ/बुजुर्ग कारीगरों को 'प्रशिक्षकों' के रूप में नियोजित किया जा सकता है।

समावेशी दृष्टिकोण

हमारे पास भारत में बड़े पैमाने पर जनजातीय आबादी है, जो गांवों में रहते हैं, वे शहरों की ओर पलायन की इच्छा नहीं रखते हैं। हमें उन्हें विकास का हिस्सा बनाने की जरूरत है। कौशल भारत, प्रत्येक आदिवासी समुदाय के लिए अद्वितीय कला/शिल्प का अध्ययन कर सकता है और अपने व्यवसाय में युवाओं को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण दे सकता है। वे अपनी भूमि, पहचान और संस्कृति को खोये बिना, नए उपकरणों और तकनीकों का उपयोग सिखाकर उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सकता है।

ग्रामीणों ने परंपरागत रूप से बड़ी संख्या में जल निकायों जैसे तालाबों, कुओं, बावडियों, नहरों आदि को संरक्षित किया है। ग्रामीणों को जल संचयन विधियों में बदलना, जल भंडारण में सुधार लाने के लिए तालाबों/कुओं का कायाकल्प करना और इन अच्छी प्रथाओं को दूसरों के साथ साझा करना, जो कठिनाइयों को कम करने में मदद करेगा। निति आयोग प्रत्येक गाँव को स्मार्ट बनाने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार कर सकता है। निजी संस्थानों या गैर सरकारी संगठनों से समर्थन आमंत्रित करें। हालाँकि, निष्पादन एक सरकारी नोडल एजेंसी के साथ रहना चाहिए।

स्मार्ट गाँव, गाँव के युवाओं को बेहतर कृषि उत्पादकता, जल संरक्षण और आर्थिक स्वतंत्रता में बदल सकते हैं। जो विकास का प्रेरक हो सकता है।

स्मार्ट विलेज के घटक

एक 'स्मार्ट विलेज' ग्रामीण समुदाय के लिए दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कल्याण गतिविधि प्रदान करेगा, जो स्थानीय प्रशासन प्रक्रियाओं में सशक्तिकरण, और बढ़ी हुई भागीदारी, उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा और अधिक सरल समुदायों का निर्माण करेगा, साथ ही साथ, एक 'स्मार्ट विलेज' सुविधा, अच्छी शिक्षा, बेहतर बुनियादी संरचना, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाएं, पर्यावरण संरक्षण, संसाधन, उपयोग दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा आदि सुनिश्चित करेगा।

गांवों के लिए सरकारी योजनाएं[6]

कृषि के लिए प्रमुख कार्यक्रम

- राष्ट्रीय कृषि विकास कार्यक्रम
- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
- उर्वरक सब्सिडी
- बैंक ऋण, मुफ्त बिजली

रोजगार में सुधार के प्रमुख कार्यक्रम

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली।
- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना।

पोषण में सुधार के लिए प्रमुख कार्यक्रम और साझेदारी सुरक्षा

- मध्याह्न भोजन योजना।
- एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS)।
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए अन्नपूर्णा योजना (ग्रामीण विकास मंत्रालय)।
- किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम।

स्मार्ट शहर -स्मार्ट गांव कार्यक्रम

स्मार्ट गावं कार्यक्रम, अलग-अलग आत्मनिर्भर क्षेत्रों में ऊर्जा, स्वच्छ पानी और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्यात्मक आवश्यकताओं का एहसास करेगा। तैयार बुनियादी ढांचे वाले गांवों के लिए, आईसीटी समाधान समुदायों के बीच कनेक्टिविटी के लिए समर्थक के रूप में काम करेंगे और ई-लर्निंग, ई-हेल्थ और ई-बिजनेस दूरस्थ पहुँच के लिए प्रदान करेंगे, जो सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगा। यह 'स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट विलेज कार्यक्रम' कार्यक्रम आईसीटीटी में टेक्नोप्रिन्योर/एसएमई के लिए नए केंद्रित बाजार को उत्प्रेरण और हरित प्रौद्योगिकी विकास जैसे कि प्रोत्साहन, आदि के अवसर प्रदान करेगा।

स्मार्ट सिटी-स्मार्ट विलेज कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

- बढ़ी हुई उत्पादकता की दिशा में कनेक्टिविटी और सूचना/ज्ञान साझा करके आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए।
- जीवन जीने, काम करने, सीखने और खेलने के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण में जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए।
- बेहतर संसाधन योजना के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के लिए एक हरियाली पर्यावरण का समर्थन करना।
- भावी पीढ़ियां विकास प्रक्रिया में अत्यधिक योगदान देंगी और आधुनिक तकनीक के उपयोग के साथ पारंपरिक कृषि गतिविधि का आनंद लेंगी।

निम्नलिखित कुछ संभावित क्षेत्र हैं, जहां स्मार्ट विलेज औसत दर्जे का और महत्वपूर्ण प्रभाव पैदा कर सकते हैं।

संगठित बस्तियाँ

गाँव की आबादी अव्यवस्थित होती है और जो मुख्य सड़कों से अच्छी तरह से जुड़ें नहीं होते हैं। इन्हें जैव-ईंधन उत्पादन केंद्र, ओवरहेड पानी की टंकी जैसी विभिन्न संरचनाओं को विकसित करने के लिए बस्ती, खेल के मैदान, कृषि भूमि और क्षेत्रों के लिए उचित प्रबंधन के साथ संरक्षित करके सुनियोजित तरीके से बसाया जा सकता है।

स्मार्ट कृषि

कृषि उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ाने के लिए खेतों को और अधिक उर्वरक बनाने के लिए सेंसर तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, जो तथाकथित 'परिशुद्धता कृषि' जिसे फार्मिंग स्मार्ट खेती 'के रूप में भी जाना जाता है, के माध्यम से जोड़ा सकता है।

सड़क का बुनियादी ढांचा[7]

जीआईएस (geographic information system) विश्लेषण सुनिश्चित करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घर ग्रामीण सड़क के माध्यम से अच्छी तरह से जोड़े जा सकते हैं।

स्मार्ट पानी की आपूर्ति

कृषि, घरेलू उपयोग और पीने के लिए पानी की आपूर्ति का प्रावधान होना

चाहिए, जो सतह और भूजल संसाधनों के प्रभावी और न्यायिक उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकता है।

स्मार्ट सफ़ाई

ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारी मुक्त गाँवों की सुविधा के लिए स्मार्ट उपकरण अपनाए जा सकते हैं, जो बेहतर सफाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

शिक्षा

गांवों के लिए अत्याधुनिक शिक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थानों को खोजने के लिए जीआईएस (geographic information system) विश्लेषण किया जा सकता है। अन्य स्थानों पर उपलब्ध विशेषज्ञों के लाभ का उपयोग करने के लिए वर्चुवल कक्षा की सुविधा प्रदान की जा सकती है।

आपदा प्रबंधन

तैयारियों के अभाव में आपदाओं से ग्रामीण आसानी से प्रभावित होते हैं। आपदा संबंधी सभी मुद्दों के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर आपदा इकाई की स्थापना की जा सकती है। आपदा इकाई भविष्य के परिदृश्यों की निगरानी के लिए केंद्रीय सर्वर के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) से जोड़ा जा सकता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि स्मार्ट गांवों के विकास में जलवायु परिवर्तन, स्मार्ट ऊर्जा, कृषि और पानी पर सरकार का ध्यान केंद्रित कराया जा सकता है । पर्यावरण योजना और समन्वय एजेंसी (EPCO) के समन्वय से राज्य में स्मार्ट ग्रामीण विकास पर काम किया जा सकता है। गाँवों में शिक्षा, व्यवसाय आदि के लिए प्रशिक्षण लेना युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में अच्छी तरह से चित्रित कर सकता है। एक शिक्षित ग्रामीण युवा देश के लिए एक संपत्ति होगा और यहां तक कि अगर वह एक शहर में शिफ्ट हो जाता है, तो वह एक एक संपत्ति के बजाय एक बोझ साबित होगा जो अब हो रहा है। भारत को शिक्षित आबादी की जरूरत है न की साक्षर, अन्यथा गांवों को स्मार्ट बनाने में विफलता होगी।

वर्तमान संदर्भ में स्मार्ट गांव का विचार अधिक प्रशंसनीय लगता है। शहरों के विकास की एक सीमा है जो शहरी जंगलों के निर्माण के लिए अग्रणी है, जहां आबादी के प्रति किलोमीटर जनसंख्या अनुपात वांछित मानदंडों से ऊपर है।

सन्दर्भ सूचि

1. https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_India
2. https://www.eolss.net/sample-chapters/13el-20-01,pdf
3. https://www.wisegeek.com/what-is-socio-econimic-development-htm
4. https://smartvillage.org
5. https://www.ourvmc.org/smartword/draft-smart-village-smartword-pdf
6. https://www.rural.nic.in/
7. https://www.gisac.org/programmes/smart-city-smart-village